

**SHRI KRISHNA CHANDRA HAL-
DAR (Ausgram):** Sir, I was trying for
the last seven days to raise this matter
regarding fall of jute price in the House.
I had tabled a Calling Attention Notice and
also sent a notice under rule 377. I am
happy that Shri Jyotirmoy Bosu has been
allowed to raise it. But, after the Minister's
statement, we must be permitted to
put questions and a discussion must be
allowed in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now
take up...

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I
thought that you would make some observa-
tions that the Minister should make a state-
ment

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has
gone on record. It would be in the interest
of the Minister to come forward with a
statement.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr.
Raghuramaiah, have you heard the Deputy-
Speaker? He has said that the Minister
should make a statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no. I
did not say that. I said that it is in the
interest of the Minister himself to come
forward and make a statement. I meant
the concerned Minister.

We now proceed to the Statutory Reso-
lution and the Bill regarding the Sick
Textile undertakings (Nationalisation)
Ordinance.

15.51 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE.
DISAPPROVAL OF SICK TEXTILE
UNDERTAKINGS (NATIONALISA-
TION) ORDINANCE
AND
SICK TEXTILE UNDERTAKINGS
(NATIONALISATION) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next
item in the agenda is the statutory resolu-
tion regarding the Sick Textile Under-
takings (Nationalisation) Ordinance; and
the Sick Textile Undertakings (Nationali-
sation) Bill follows that item. The two
will be taken together. The time allotted
is six hours.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur):
Sir, just one minute. There are many
provisions regarding this Bill and some are
very controversial. We are told that in
certain matters of safeguarding the interests
of the textile workers, such as the social
benefits in respect of pension, gratuity
and provident fund, some important steps
are being taken. We met the hon. Minister
Mr. Maurya—I am thankful that he is
bringing some amendments—and we also
met Mr. Pai. Certain things were agreed
to. And now I learn that the law officers
are objecting to provident fund. Because
this is not going to the Select Committee,
I submit to you and through you to the
hon. Minister....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you
speaking on the Bill?

SHRI S. M. BANERJEE: ...because
the ordinance will have to be converted
into a Bill, that if the hon. Minister can
call a meeting of the Opposition Members
tomorrow—my amendments will come
tomorrow—we could have a formal or
informal discussion so that some decision
can be taken and the workers may be
helped.

श्री मधु लिनये (गंका): उपाध्यक्ष
महोदय, यह एक बहुत महत्व विषय है
और इस के सभी पहलुओं पर चर्चा होनी
चाहिये, ऐसी मेरी राय है। एक सिद्धान्त
के तौर पर मैं अध्यादेश के द्वारा कानून पास
करने का विरोधी हूँ क्योंकि उसका नतीजा

{की वह नियमों}

में होता है कि जल्दबाजी में भाप को विधेयक के द्वारा जो संसद का सब होता है उसमें फल करना पड़ता है। नतीज यह होता है कि भाप किसी संलेक्ट कमेटी या जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के पास उस को नहीं भेज सकते, और अनुभव यह है कि जब कोई विधेयक संलेक्ट कमेटी या पार्लियामेंटरी जोइंट कमेटी में जाता है तो में वह नहीं कहना कि वह सुनत दीर्घकाल हो जाता है, लेकिन मेरी राय में वह ज्यादा अच्छा बिल हो जाता है। तो इसलिये मैं इस का विरोधी हूँ। लेकिन इस आडिमेंस का जो प्रभाव है कि जब तक जो सूती मिलें सवालको के द्वारा ठीक से नहीं चलाई गई बिल की बजह से, वह बन्द हो गईं उन मिलों को हाथ में ले कर अब राष्ट्रीयकरण करने का जहां तक प्रभाव है उस से मैं सहमत हूँ। मेरी यह राय है कि वह जो 103 मिलें हैं, भाप कुछ राज्यों के कारपोरेशन के तहत हैं और कुछ राष्ट्रीय कारपोरेशन के तहत हैं। मेरी राय में सूती मिलों को भाप राष्ट्रीय कारपोरेशन के तहत दीजिये। लेकिन मुँक में राज्यों की स्वायत्तता की हथिया समर्थक हूँ मैं चाहना कि जिन राज्यों में यह मिलें अधिक सख्या में हैं उन राज्यों के प्रतिनिधि भाप बोर्ड आफ गवर्नेट्स और मैनेजमेंट में ले लीजिये। दूसरी बात यह है कि भाप रीजनल बोर्ड्स भी विकेंद्रीकरण के सिद्धान्त के आधार पर बनाइये और उस में राज्यों की अधिक प्रतिनिधित्व दीजिये। ऐसा मैं क्यों सुझा दे रहा हूँ? क्योंकि एक कारपोरेशन के तहत यह

बाकी मिलें यदि वा जालेंगी तो बुरे देश की जो टेक्स्टाइल पीमिटी है उस को ठीक विधा में भाप प्रभावित कर सकेंगे। वेरना राज्यों के बीच में प्रभाव संबंध धर्मर मोतिया चलेंगी तो उस में संबंध एकसाथ उत्पन्न हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि यह जो 103 मिलों का भाप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं इसमें लूमेज स्पिन्डलेज और मजदूरों की सख्या कुल टेक्स्टाइल इन्डस्ट्री में जितना लूमेज है, स्पिन्डलेज और मजदूर हैं, उस का 18 और 22 प्रतिशत के बीच में भाप राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार के नियंत्रण में ले रहे हैं। तो ऐसी हालत में इस बिल को एक तीवर के तीर पर इस्तेमाल करना चाहिये एक मुकम्मल सोकान्मुक टेक्स्टाइल नीति की चलाने के लिये।

सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाप हमारी टेक्स्टाइल इन्डस्ट्री में कपड़े की कितनी बैराइटीज मिलों द्वारा पैदा की जाती है? लगभग 4,300 प्रकार। तो मेरा मुद्दा यह है कि क्या इतनी बैराइटीज की जरूरत है देश की? इसलिये बहुत बड़े पैमाने पर इन प्रकारों की संख्या को घटा कर कुछ स्टैंडर्डाइज्ड बैराइटीज इन लोगों को पैदा करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

एक दूसरी विभिन्न बात यह है कि यह 103 मिलें जो अधिकांश संसाधन के अभाव में हैं, लेकिन जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं, वे संसाधन के तहत

घाबेंगी। यह सब मनुष्य ही का चक्कर था, यह पावर स्टैटर के भीर उन्हींने अपना साम्राज्य फैलाते फैलाते यह उद्योग के लोको में ही आक्रमण करने लगे थे। मेरी राय है कि पूरी टेक्सटाइल मिलों को एक ही मंत्रालय के तहत रखना चाहिये, चाहे उद्योग मंत्रालय ही या व्यापार मंत्रालय ही। मेरी राय में उद्योग मंत्रालय में इन को आना चाहिये। व्यापार मंत्रालय में मनुष्य ही का इतलिये बीबा या नियमित के लिये। लेकिन कुल उत्पादन का कितना घंटा निर्धारित करती है यह मिलें? अधिकतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मरीच जनता की कपड़ा दिलाने के लिये हैं। इतलिये पूरी काटने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उद्योग मंत्रालय के तहत लाना चाहिये। भाप भी जरा इस बारे में प्रधान मंत्री से बात कीजिये।

टेक्सटाइल मिलों द्वारा जनता की जो सेवा की गई है उस के बारे में जरा विचार को देखिये। खेद की बात है इस में ही सरकार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों को जिम्मेदार समझता हूँ। इस इंडस्ट्री का काम है कि जनता के लिये न्यूनतम कपड़ा तैयार करे। लेकिन खेद की बात है कि 1964 के बाद फी व्याप्त कपड़े की उपलब्धि लोगों के अभाव पटती चली जा रही है। मैं भी एक वर्षों हूँ। 1964 में पर कैपिटल अवेरिजिडिटी घाट 15, 22 मिलियन लेकिन 1973 में मिलते यह 11, 57 मिलियन ही रहे। तो किसी तरह की देह की ही रही है और आंतरिक उत्पादकों के लिये

घाप के राज्य में क्या हो रहा है इस का यह परिचायक है।

दूसरी एक भजेदार बात यह है कि जो इंडियन और पावर लुब का खेद है उसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अविश्वस्य से निपटाया है और अपनी फैसला 30 करोड़ मिलियन तक बढ़ाई है जबकि 1964 और 1974 के बीच में मिन खोला मिलों की मिलों की खोला खोले 30 करोड़ मीटर कपड़ा कम तलसे सब काराकिय है मरी इंडस्ट्री और पावर लुब का जो उत्पादन इतलीक बढ़ाई 30 करोड़ मीटर काक की बावें बाइक मिन मीटर मिनियल बढ़ाई मिनियल मिनियल। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो सेवा है, उसके अन्तर्गत प्रकाश पड़ता है इस उद्योग पर में अतिरिक्त समझना चाहता हूँ कि राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी की उद्योगो उसने कीक तरह नहीं निभाया। यह अतिरिक्त इतलिये अतिरिक्त मन्वीर हो जाता है कि मन्वीर भाप प्रतिगत ने देखे जो इस साल पहले 4064 में 80 प्रतिशत कपड़ा मिलों के द्वारा पैदा किया जाता है और अन्त-साल के अन्त 51 प्रतिशत पैदा किया जाता है और पहले इंडस्ट्री मरीच पावर लुब मीटर के द्वारा 49 प्रतिशत किया जाता था, अब 30 प्रतिशत किया जाता है। इसका अन्तक्य है कि अतिरिक्त खेद ने अपने सामाजिक-आर्थिक को निभाया है और अतिरिक्त मिन-आर्थिकों के अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है।

एक और खेद में मिन अन्तर्गत अपने अतिरिक्त मिनियल को पूरा नहीं कर, यह इतिरिक्त खेद सरकार उद्योग मन्वीर का अतिरिक्त मन्वीर

बड़ा है, अम्बिका मिल का 75 प्रतिशत बढ़ा है, टाटा मिल का 50 प्रतिशत बढ़ा है, बाम्बे डाईंग का 45 प्रतिशत बढ़ा है और विनोद मिल जो उज्जैन की है उसको तो 62 लाख रुपये काटा हुआ था 1971 में लेकिन दो साल ऐसी लूट उसने मचाई कि 1973 में उसने 1 करोड़ 68 लाख रुपये का मनाफा कमाया घाटे को एकदम नफे में परिवर्तित कर लिया गया। गरीब जनता को कपड़ा पहनाने के मामले में यह इंडस्ट्री पूर्णतया असफल हो चुकी है और इन लोगों को अच्छी फटकार पालियामेंट से और जनता से मिलनी चाहिये यह मेरी राय है।

अब मैं उस सवाल पर आना चाहता हूँ जिसमें साधारण जनता की बहुत दिलचस्पी है कि नियंत्रित कपड़े के बारे में आज तक स्थिति बिल्कुल असन्तोषजनक रही है। बार-बार आश्वासन दिया गया है कि साधारण जनता के लिये नियंत्रित कपड़ा आप बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या है? 1971 में, मैं मिलों की चर्चा कर रहा हूँ, कुल के उत्पादन में 10 प्रतिशत आपने जनता के लिए नियंत्रित कपड़ा बनाया, फिर 1972 में यह 16 प्रतिशत हुआ, 1973 में गिर कर 14 प्रतिशत रह गया। 1 अप्रैल 1974 को आपने घोषणा की कि 80 करोड़ मीटर कम से कम कंट्रोल का कपड़ा हम लोग बनाएंगे। यह कुल मिलाकर 20 प्रतिशत हो जाएगा। 80 करोड़ मीटर बनेवा तो 20 प्रतिशत आप कह सकते हैं कि कंट्रोल का कपड़ा होगा। मेरी राय है कि इसको 30-35 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिये। आज क्या हो रहा है पहले एक नियम था कि निर्धारित कोटा अगर कोई मिल पूरा नहीं करेगी तो एक मीटर के पीछे

एक रुपये जुमनि के तौर पर देना पड़ेगा, लेकिन मिलें जो सुपरफाइन और फाइन कपड़ा बना रहीं थीं छात कर लोग स्टेपल काटन का हस्तेमाल करते उनको चार-पांच रुपये का मुनाफा होता था, मिले क्या करती थीं? जुमना देती थीं और कंट्रोल का कपड़ा बनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती थीं। उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे कि कंट्रोल का कपड़ा बनाने के अपने दायित्व को पूरा तो नहीं करते थे लेकिन जो जुमना एक रुपये मीटर के हिसाब से पहले था उसमें भी बकाया उनकी तरफ था और उनमें सब से बड़े कपाड़ियां हैं। श्री भीर्य इस मंत्रालय में नये प्राचनी हैं। मैं उन से जानना चाहूंगा कि चूकि कपाड़ियां मासूति में बड़े लोयर डोल्वर हैं, इसलिये क्या वह उन के सारे पापों पर पर्वा डालेंगे, कुल बकाया जुमनि का 50 प्रतिशत से अधिक कपाड़ियां के नाम से हैं। ये तो समाज विरोधी लोग हैं, और आप लोग उन को रेसपेक्टिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि मासूति में उनकी दो कम्पनियों स्लाटिड एंगल्ड लिमिटेड और किलिक स्लाटिड मशीन्स लिमिटेड ने पैसा लगाया है। आप ने उन को नैशनल रेवन कर्पोरेशन पर भी कब्जा करने दिया, काहेनूर मिल बम्बई की एक बड़ी मिल है। जब वह उनके हाथ में आई, तो उन्होंने उस में से जो कर्बों के रूप में पैसा निकालने का काम शुरू किया।

फिर सरकार ने जुमनि को बढ़ा कर ड्राई रुपये प्रति मीटर कर दिया। यह अच्छी बात है। लेकिन उस में रिलेक्सेशन क्यों शुरू हो गया? इसमें चुपचाप यह है कि अगर मिलें कंट्रोल कपड़े के उत्पादन में एक मीटर का डिफाइट करें, तो उनको 5 रुपये का कपड़ा या

[श्री मधु लिमये]

7-50 रुपये के गॉरमेंट्स निर्यात करने होंगे, और उन का जुर्माना माफ हो जायेगा। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह के रिलेक्सेशन से कंट्रोल्ड कपड़े के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल्ड कपड़े के बारे में सरकार की जो नीति है, वह महजमखोल और फ़ार्स बन गई है। टैक्सटाइल कमीश्नर और व्यापार मंत्रालय के अधिकारी दोनों मिलकर मिल वालों से बहुत पैसे ले रहे हैं और राजपुरुष भी ले रहे हैं। इस लिये उनके द्वारा जो जन-विरोधी काम हो रहे हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो सरकार नियंत्रित कपड़ों की पैदावार कम से कम 30-35 प्रतिशत तक बढ़ा दे, निर्यात के लिये यह ढील नहीं होनी चाहिये और वह सभी मिलों से कहे कि वे अपना कोटा महावार या कम से कम क्वार्टर्ली बेसिस पर पूरा करें, एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे दस ग्यारह महीने तक अपना कोटा पूरा नहीं करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बाजार में कंट्रोल्ड कपड़ा कम हो जाता है और उस के दाम बढ़ने लगते हैं और सरकार कंट्रोल्ड कपड़ों की स्टेडी सप्लाई चाहती है, तो यह आवश्यक है कि मिलों की यह जिम्मेदारी हो कि वे हर महीने कंट्रोल्ड कपड़ों का निर्धारित कोटा पूरा करें कम से कम त्रैमासिक बेसिस पर यह होना चाहिये।

नियंत्रित कपड़ों के वितरण में बड़े घोटालों हैं। एस्टीमेट्स कमेटी के सामने सरकार ने यह कबूल किया है कि वह होलसेलर्स या नैशनल

को-ओपरेटिव फेडरेशन या दूसरी को-ओपरेटिव सोसाइटियों को वितरण के लिये जो कपड़ा देती है उस के बारे में बड़ी शिकायतें हैं। इस लिये मेरा सुझाव है कि अनाज और चीनी के लिये जो वर्तमान पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उस को सरकार चुस्त बनाये और उस में जो भयंकर भ्रष्टाचार है, उस को निकाला जाये। राशन कार्डों पर कंट्रोल्ड कपड़ों का वितरण गरीब लोगों में ठीक ढंग से होता है या नहीं, सरकार नागरिक समितियाँ, सिटिजन कमेटीज बना कर उसकी देखभाल करने का प्रयास करे।

इस बारे में एक और सुझाव यह आया था कि कंट्रोल्ड कपड़ों के हर मीटर पर स्टैम्प लगनी चाहिये। आज यह होता है कि कपड़ों के तामों के शुरू और अंत में प्राइस स्टैम्प लगती है लेकिन जब पहला मीटर बिक गया तो गरीब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कपड़ों का क्या दाम है। मुझे याद है कि तीसरी लोक सभा में डा० राम मनोहर लोहिया ने इस तरह के बिल्लू भी यहां पेश किये थे कि आदिवासी इलाकों और हरिजन बस्तियों में जो दुकानें हैं, उनके द्वारा किस तरह की लूट होती है। साधारण आदमियों को अनियंत्रित कपड़ों के दामों पर ही यह कपड़ा बेचा जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर मीटर पर प्राइस स्टैम्प लगनी चाहिये और वह जनता की भाषा में होनी चाहिये। तमिलनाडु में वहां के अंकों में होनी चाहिये और हिन्दी भाषी इलाकों में हिन्दी अंकों में होनी चाहिये।

इस विधेयक में मुआवजे के लिये जो प्रावधान रखे गये हैं उनके बारे में कुछ विचित्र किस्म की बात है। मैं एक मिल का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल दो

उदाहरण देना चाहता हूँ। घाण्ड प्रवेक्ष में वारंशल की प्राइवटाइजी मिल का 100 रुपये का शेयर उस के मिसमैनेजमेंट के कारण गिरते गिरते माइन से 190 रुपये हो गया, जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीद किया गया मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार उस मिल को जो 93 लाख रुपये का मुद्रावजा देने जा रही है, वह किस आधार पर और उस की क्या व्यापारिक कमीटियाँ हैं।

दूसरी मिल है एपोला मिल, जिस को 1,20,00,000 रुपये का मुद्रावजा दिया जा रहा है। यह गोकुलचन्द मोरारकाज की मिल है। और गोकुलचन्द मोरारकाज कितने बूझ के धोये हुये है, उस के बारे में कुछ कह कर मैं अपना समय क्यों बिताऊँ। इनको मैं वामानी साहब पर ही छोड़ देता हूँ। ऐसे मामलों में उन को ही बोलना चाहिये। सब तरह के फ्राइड, चार सौ बीस और गन्दे काम गोकुलचन्द मोरारकाज ने किये हैं। लेकिन सरकार फिर भी बड़ी दयालु है, जो उन को 1,20,00,000 रुपये का मुद्रावजा दे रही है।

अब मैं एक इनिवादी बात पर आता हूँ। ये टेक्स्टाइल मिलें पहले प्राइवेट मैनैजमेंट के अन्तर्गत थी फिर सरकार ने उन को अपने हाथ में ले लिया और अब उन का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। उन मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं को संबोधित किया जा रहा था। मैं श्री बुद्धिप्रिय मोर्य का अभिनन्दन करता हूँ और उन की मराहना करना हूँ कि उन्होंने अपनी तरकीबों के द्वारा उन लोगों की कान्टीन्सुइटी फ्राऊ सविस को बने रहने दिया है यह बहुत ही अच्छी बात है।

श्री राज सहाय चौडे (राजनंदगाव) :
घाण बड़ी मुश्किल से सराहना करते हैं।

श्री जयु सिन्घे : घाण मुश्किल से अच्छे काम करते हैं।

टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की कन्डीशन्स फ्राऊ बर्क कैसी होती हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। फ्राऊ कल बम्बई के दवाओं के कारखाने क्लिनिकली मुड होते हैं। और ऐसे लगता है कि वे बागीचे हैं। ऐसी कन्डीशन्स टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में नहीं होती हैं। वहाँ मजदूरों ने अपना पसीना बहाया है और खून बहाया है। उन में से कई लोगों को टी० बी० हो गया है। उन लोगों ने मेहनत कर के जो ग्रीडुटी और प्राविडेंट फण्ड कमाया है, इम विधेयक के सिड्यूल में चांजिज की सूची में उस को कितनी लो प्रायटी दी गई है। इम में दल-विधेय का सवाल नहीं है। मैं केवल विरोध पक्ष के सदस्यों से ही नहीं, बल्कि उधर के सदस्यों से भी—इन्डोर के श्री रामसिंह भाई बैठे हुए हैं, जो टेक्स्टाइल मजदूरों के बड़े नेता है—अपील करना चाहता हूँ कि वे इस बारे में हमारी मदद करें। मैं चाहता हूँ कि सब से पहला चांज मजदूरों का प्राविडेंट फण्ड, ग्रीडुटी और उन के दूसरे ब्युज होने चाहिए।

श्री राज सहाय चौडे : जुक से ही।

श्री जयु सिन्घे : मैंने प्री-टेक घोषण का एनेषमेंट किया है। सिन्धुई लोन्ड कर्नरहु बाद में आते हैं। मजदूरों के पसीने से पैदावार और सम्पत्ति उत्पन्न होती है। इस के लिए कार्ल मार्क्स का किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्राथमिक सत्य आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस को प्राथमिकता दे।

[श्री मधुसिन्धु]

मैंने जिसे टैक्सटाइल नीति की और हस्तार किया है, मैं चाहूंगा कि उसको कार्यान्वित करने के लिये नेशनल टैक्सटाइल कोरपोरेशन और राष्ट्रीयकृत मिलें एक नबीर पेश करें। कैसे कन्ट्रोल्ड क्लाय के उत्पादन के बारे में अगर दूसरे लोग चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, बिफास्ट करते हैं, तो नेशनल टैक्सटाइल कोरपोरेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर सारा चाटे का ही सीधा होगा, तो राष्ट्रीयकृत मिलें हमेशा चाटे में रहेंगी, और बदनाम भी हो जायेंगी कि उनमें हमेशा चाटा होता है। इसलिये जहाँ कंट्रोल कपड़े के उत्पादन को 30 प्रतिशत बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इसकी भी मांग करूंगा मैं समर्थन करूंगा कि रीजनेशन प्राइस कंट्रोल क्लाय का होना चाहिये वरना आप का नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन चल नहीं पायेगा। यह मैं मानता हूँ।

और मैं एक बात यह कहूंगा कि आप की जो स्पिननिंग मिल्स हैं, कम्पोजिट मिल्स की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका एक विशेष दावित्व होगा कि हैंडलूम और पावर लूम के लिये जिस काउन्ट का सूत चाहिए वह उन को दें। ये प्राइवेट सैक्टर की मिलें बड़ी बदमाशी करती हैं, दो तीन साल पहले इतना कम हैंडलूम और पावर लूम बालों को इन्होंने दिया, मेरे क्षेत्र में हैंडलूम और पावर लूम बाले लोग हैं, लोग तंग आ गये, सूत का दाम बढ़ाया गया, आम-जनी लिया गया, इसलिये मेरा सुझाव है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की स्पिननिंग

मिल्स को हैंडलूम और पावर लूम बालों को उचित काउन्ट के सूत की स्टेडी सप्लाय करने का जो बड़ा काम, बड़ा दावित्व है उसको लेना चाहिए और मिथी मिलों के ऊपर भी उसी तरह का एक निर्वहन लगाना चाहिए। ... (व्यवधान) ... मैं वही कह रहा हूँ। जब यहाँ नहीं करेंगे तो प्राइवेट सैक्टर को भीका मिल जायेगा कि बुद्धिधिय मीयें का कोरपोरेशन ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करे? तो आप करिये और प्राइवेट सैक्टर ने भी करवाइये।

श्री राज सहज्य पांडे : नबीकरण भी करिये।

श्री मधु सिन्धु : मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मेरा दूसरा महा तो यही था—प्राधुनिकीकरण और नबीकरण के बारे में और उसके बारे में मैं बहुत चिन्तित हूँ क्योंकि एक विशेषज्ञों की कमेटी ने कहा था कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के प्राधुनिकीकरण और नबीकरण के लिये 1250 करोड़ की आवश्यकता है। उनमें नेशनलाइज्ड मिलों का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वह कम से कम 250 करोड़ आता है, 250 करोड़ आप को खर्च करना पड़ेगा। तो जो मिलें अच्छा निर्यात का काम कर रही हैं प्राइवेट सैक्टर में उनको आप वरीयता देंगे तो बान समझ में आयगी लेकिन सबसे पहले नबीकरण और प्राधुनिकीकरण की प्रायोरिटी आप को नेशनलाइज्ड मिलों को देनी चाहिए। उसके लिये आपने कुल कितना प्रोवाइड किया है? आप ने 108 करोड़ की व्यवस्था की है। वह भी होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आवश्यकता है 250 करोड़

की और 108 करोड़ भी नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होगा उसके बारे में अभी से आप सोच लीजें। पचास प्रतिशत सिर्फ जो आपने किया वह उचित नहीं है।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज की राष्ट्रीयकृत मिलां को प्राधुनिकीकरण, कपड़े की पैदावार बढ़ाना, उत्पादन का खर्च घटाना, बिजली के दामों को गिराना, इन सब के बारे में पेंस-मेंटर का काम करना चाहिए और फिर नीजी क्षेत्र में भी इसी तरह का दबाव डाल कर उनसे भी इसी तरह का काम आप को कराना चाहिए। अभी-प्रती इंडस्ट्रियल रिजेशन की बात जो भी करा सरकार इस बात के लिये बहुत जल्दी प्रयास करेगी कि विगत दो तीन वर्षों में बहुत ही अन-रीजनबल ढंग से कपड़े का दाम बढ़ाया गया तो मेरी राय में कम से कम 25 से 30 प्रतिशत तो सभी वैरा-इटीज के कपड़े का दाम आप घटाने के लिये कहिये। आज मिलां ने कई बहाने बना कर अपना उत्पादन घटाने का काम चलाया है। इसका नतीजा क्या होगा कि आज तो मांग कम हो गई। क्यों हो गई कम? एक तो बहुत सारे लोग फ्लड अफेक्टेड, फेमिन अफेक्टेड हैं, अकाल और भुखमरी आदि के चलते लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। इसलिये हल्ला हो रहा है। इसलिये दाम घटाना बहुत जरूरी है।... (श्वबधान)...

क्रेडिट की जहां तक बात है मैं भी मानता हूँ कि क्रेडिट पालिसी सलेक्टिव होनी चाहिए, धन्वी नहीं होनी चाहिए। इनकी क्रेडिट पालिसी धन्वी पालिसी है। स्केलेटर्स के लिये भी, होटर्स के लिये भी एक ही कानून

है और जो उत्पादन के काम में लगे हुये हैं उनके लिये भी एक ही कानून है। तो यह मामला इंडस्ट्री मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ लेना चाहिए। यह क्रेडिट पालिसी धन्वी न हो, उत्पादन उन्मुख हो। और उत्पादन भी रैफ़िजरेटर, एयर कंडीशनर और टेली-विजन आदि का न हो कर जो कन्स्यूमर गुड्स है, या कैपिटल गुड्स हैं उनका हो। तो यह भी एक इसका पहलू है।

अब नेशनल काटन कारपोरेशन का जो काटन मोनर्स है, किसान हैं जो रुई पैदा करते हैं, उनके प्रति कोई दायित्व होगा नहीं? भीम जी को पता होगा कि सितम्बर, 1974 से नवम्बर, 1974 तक दो तीन महीनों के अन्दर काटन कारपोरेशन की गलती और अयोग्यता के चलते, व्यापार मंत्रालय की नालायकी के चलते किसानों के साथ अंधकर अन्याय हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में इसाके सारे कपास के इसाके हैं। किसान मर रहा है जूट की कहानी अभी ज्योतिर्मय बसु ने बताई। लेकिन जनता से नीचा जो सम्पर्क रखता है वह तो कपड़े का सबाल है। इसलिये काटन के बारे में आप को ज्यादा सचेत रहना चाहिये। मैं केवल तीन आंकड़े दूंगा। कल्याण जाति का जो काटन है इसका दाम सितम्बर में 4200 रुपये प्रति कैंडी था और नवम्बर में 2500 ०० प्रति कैंडी हो गया। इसकी गिरावट आ गई। इसी तरह बिम्बिजब रई जो है उसका 4600 रुपये था सितम्बर में और नवम्बर में 3150 रुपये हो गया। इसी तरह संकर 4 जो वैराइटी है उसका दाम था 5800 रुपये सितम्बर में और नवम्बर में

[श्री मधु लिमये]

करीब करीब 4200 रुपये प्रति कैंडी हो गया। इसलिये मैं यह कहूंगा कि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को भी घब घब मैदान में उतरना चाहिए। बैंकों की उनको क्रेडिट देनी चाहिए। काटन कारपोरेशन घगर मालायक है तो घ्राप को भी अघोष्यता का प्रमाण नहीं देना चाहिए। कुछ किसानों के प्रति भी घ्राप का घपना जो वायित्व है उसको घ्राप पूरा किजिये। दूसरे मामलों में भी तुरा किजिये।

अन्तिम बात मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा काम घ्राप करने जा रहे हैं तो इसके सचालन के जो तरीके हैं उनमें भी घ्राप को कुछ परिवर्तन करना चाहिए। 27 साल का अनुभव है कि जो भी राष्ट्रीयकृत कारपोरेशनस होते हैं उनमें जो अधिकारी होते हैं वे सोचते हैं कि यह घपने घ्राप की जायदाद है तो एग्याबी के ऊपर, फिजूलखर्ची के ऊपर और बिलासिता के ऊपर पैसा बहुत सारा खर्च किया जाता है। मजदूरो के बेतन घ्राप बढ़े लोगों के बेतन घ्राप सुविधाओं को घ्राप मिलाइये, इतना बड़ा फर्क घ्राप देखेंगे तो यह समाजवाद का बात भी लेना घ्राप इतनी बिकसता घ्राप और और-बराबरी को बढ़ाते जाना, बर्बादी को बढ़ाते जाना यह एक बहुत बड़ा पाप है जो घ्राप लोग कर रहे हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो उपबीकता है घ्राप अम करने वाले जो मजदूर हैं क्या इन जिलों के संचालन में इन को भी कोई हिस्सेदारी घ्राप देंगे? घ्राप के बिल में कोई चीज है इसके बारे में? इसलिये इतना बड़ा, यात्री 22 प्रतिगत टैक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको घ्राप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं,

उसमें तकरीबन 22 या 20 प्रतिगत मजदूर काम करते हैं कुन टैक्सटाइल इंडस्ट्री के, फिर भी घ्राप ने उनके लिये कोई प्रावधान नहीं रखा। तो घ्राप के जो मैनेजमेंट के घ्राप तक के तरीके रहे हैं उनमें घ्राप कुछ बुनियादी परिवर्तन कोजिये, नये प्रयोग कीजिये। युगोस्लाविया में बर्कस मैनेजमेंट की बात चल रही है, दूसरे देशों में भी विभिन्न प्रयोग किये जा रहे हैं।

श्री राम सहाय बांडे पाटिसियेसन इन मैनेजमेंट।

श्री मधु लिमये : वहीतो मैं कह रहा हूँ। उसके बारे में मैं कोई डागमेटिक नहीं हूँ कि इसी एक फार्म को ले लीजिये। लेकिन घ्राप को यह प्रयोग करना चाहिए।

रीजनल बोर्ड की बात मैंने इसलिये की कि थोड़ा एक कम्प्रीटीशन का भी एनीमेंट जरूर होना चाहिए जिससे कि विभिन्न रीजनल बोर्ड्स में यह होइ लगे कि कौन बढ़िया ढंग में काम कर रहा है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं सकल्प को घ्राप-चारिक ढंग में पेश कर रहा हूँ। यह समा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित रन कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) प्रख्यादेश, 1974 (1974 का अघ्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

MR. DEPUTY-SPEAKER : Resolution moved :

"This House disapproves of the Sick Textile undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974 (Ordinance

No. 12 of 1974) promulgated by the President on the 21st September, 1974."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA) : The Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill was introduced in the Lok Sabha on the 2nd September, 1974. The hon. member, Shri Limaye raised an objection that in principle he is against the Ordinance.

I would like to reply to this first and then come to other relevant points he raised.

16.30hrs. (SHRI VASANT SATHE
in the Chair)

Before proceeding further, I would mention in the very beginning that barring the bitterness which the hon. member has got for the Nehru family and its members—I am not going to involve myself in replying that bitterness because whatever bitterness he has shown, that is his personal feeling—regarding rest of the things he has given very sound proposals which will help not only the workers and the industry but also the entire nation. Some of the points he made are already being agreed upon and I would like to mention them during the course of my observations.

Regarding the Ordinance, hon. members are aware that the load of government business awaiting disposal was heavy. The House was considering the Finance Bill introduced in connection with the supplementary budget. The Bill had to be passed so that the relevant provisions could be brought into effect. The import licence case which was not earlier on the agenda became an explosive issue and took up a good deal of time. The Constitution (Thirty Sixth Amendment) Bill relating to Sikkim was also brought up for consideration. Under these circumstances, the Business Advisory Committee of the House could not allot any time for discussion of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill before the House was prorogued on 9 September, 1974.

As inevitably there was to be a gap of about three months between the introduction of the Bill in the last session and its consideration in the present one for reasons discussed below, it was considered necessary to promulgate the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance on 21 Sept. 1974. Firstly, there were 6 textile undertakings the management of which could not be taken over by Government on account of stay orders passed by courts. The possibility of transfer of assets by the owners of these undertakings could not be ruled out. It was necessary to take over the possession of these mills to obviate such a possibility. Secondly, the owners of these sick undertakings knowing the provisions of the Bill could enter into contracts which would be detrimental to the interest of the undertakings. Thirdly, since the liabilities pertaining to the takeover of the management were not being assumed by the Central Government but were to be paid out of the amounts provided under the First Schedule on the basis of claims to be filed before the Commissioner of Payments, certain creditors had begun to pressurise the managements to discharge these liabilities before the actual nationalisation of the undertakings. In these circumstances, in case the managements succumbed to such pressures, considerable losses could have been caused to the undertakings and the intention of laying down the order of priorities under the Second Schedule for discharge of claims would have been defeated.

At this stage, I may also be permitted to mention that in similar circumstances in the past also it had become necessary for Government to issue Ordinances after introduction of the relevant Bills which could not be enacted into law in time.

I am sure hon. members would appreciate the weighty considerations which impelled Government to promulgate the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1974 on 21 September, 1974 when the relevant Bill could not be taken up for consideration in the last session of Parliament. The Sick Textile Undertaking

[Shri B. P. Maurya]

(Nationalisation) Bill 1974 now seeks to replace the Ordinance which has been promulgated.

I would appreciate the feeling of Shri Madhu Limsaye who had high appreciation for the step, the Government took of nationalisation. He has said some things which are already being followed by Government. He said during his speech that 25-30 per cent of the prices should be pulled down. This is already the policy of the National Textile Corporation and it will be implemented in due course.

He has also given valuable suggestions about other things, but he himself has suggested in his speech that the textile industry is controlled by two Ministries, and the hon. Member took objection to it. One part of it is controlled by the Ministry of Commerce and Foreign Trade and the other part is managed by the Ministry of Industry. I would like to mention that most of the portion contained in his speech are concerned with the Commerce Ministry. So, I would not like to take the time of the hon. House in replying to those questions because they are mainly concerned with the Commerce Ministry.

Before I move for consideration, I would like to draw the attention of the hon. Members to certain salient features of this Bill. Under clauses 3, 4 and 5, the right, title and interest of the owners stand transferred to and vest in the Central Government free of all encumbrances. We are moving amendments to sub-clause (1) of clause 4 and clause 5 of the Bill to make it clear that besides the assets acquired, certain liabilities, viz., loans advanced by the Central Government or State Governments or by the National Textile Corporation/State Textile Corporations, and wages, salaries and other dues of employees relating to the post-take over of management period shall be the liabilities of the Central Government, and the said liabilities will be discharged for and

on behalf of the Central Government by the National Textile Corporation. The provisions in Chapter III refer to payment of amount to the owners of the sick textile undertakings for the transfer to and vesting in the Central Government of the right, title and interest of the owner in relation to the sick textile undertaking.

Chapter IV refers to the management of the sick textile undertakings through the National Textile Corporation which is empowered to exercise powers in this behalf. It may be stated that clause 6 empowers the National Textile Corporation to set up subsidiary corporations. Chapter V contains provisions relating to employees of the undertakings. Clause 14 clarifies that all employees of the undertakings shall become employees of the National Textile Corporation on and from the appointed day and continue to draw the same emoluments and have similar rights as they were enjoying previously. Chapter VI deals with the appointment of Commissioners of Payment and the procedure for making payments. Under clause 18, the Central Government has to pay to the Commissioners within 30 days from the specified date the amount indicated in the First Schedule. Under clause 20, every person having a claim against the owner of a sick textile undertaking has to prefer the claim before the Commissioner. The priorities of the claim have been indicated in clause 21, which is to be read with the Second Schedule.

In this Bill, a clear distinction has been made between liabilities of the undertakings for the post-take over if management period and those pertaining to the pre-take over of management period. It was considered necessary that priority should be accorded to liabilities incurred during the period. The management of the undertakings remained with the Central Government since the Government had, with the loans and other credits obtained, made investments or modernisation and

rehabilitation of the mills. It was necessary to ensure that the creditors placed in Category I of the Second Schedule who had helped the Government during this period to undertake such rehabilitation and modernisation of mills should have their liabilities fully protected. Therefore, it has been provided under clause 27 that where any liability arising out of any item specified in Category I of the Second Schedule is not discharged fully by the Commissioner out of the amount, the Central Government shall assume the liability to the extent it remains undischarged.

In the case of liabilities pertaining to the pre-take over of management period, these have been placed under Categories III, IV and V of the Second Schedule. The creditors concerned will have to file claims before the Commissioners of Payment for settlement of these liabilities out of the amount paid to the owners under the First Schedule. Under Clause 24, the procedure for payments to claimants and under Clause 25 to the owners of the balance left over after meeting the liabilities as specified in the Second Schedule has been laid down.

Chapter VII deals with miscellaneous provisions. It is pertinent to state that the interest of employees of the mills have always been kept in view by the Government. For the post take over of management period, all employees' dues are being fully protected and they are not required to file any claims for satisfaction of these dues before the Commissioners of Payment.

In regard to the pre-take over of management period also, the employees' dues have been given a priority only next to the secured creditors. It may also be clarified that in respect of employees whose services are transferred to the NTC or its subsidiaries after nationalisation, the entire period of their service will be taken into account for determination of amount of gratuity and pension payable to them.

The future management pattern of these textile undertakings has been worked out keeping in view the requirement of efficient

and co-ordinated management on a uniform pattern throughout the country.

One point was raised by an hon. Member. The State Governments have been given the option to participate in the equity to the extent of 49%. The management will be looked after by the National Textile Corporation. Under the National Textile Corporation there will be 9 subsidiary corporations. In these subsidiary corporations the States will have the right to purchase shares up to 49%. 51% will be the share of the Centre.

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay-North East) : What will be the right of State in the management.

SHRI B. P. MAURYA : I should like to go into details when we take up clause by clause consideration. This has been done in order to avoid heterogenous organisations and to have one uniform pattern so that the workers could get their dues and the consumers also could get cloth at a fair price. Keeping these factors in mind this decision has been taken so that there can be one uniform pattern of management. No doubt that will be helped by the 9 subsidiary corporations. The States will be given their shares so that they will not lose interest. When the Chairman-cum-Managing Directors are appointed they will definitely be appointed in consultation with the States Governments. When we come to clause by clause discussion we can discuss the detail. At this stage my submission to the hon. Member is that the idea is to organise this industry in such a way that we produce the maximum and we produce such articles which are used for domestic consumption. When we produce articles which are to be used for foreign market, in that case also a uniform system will definitely help.

It is worth mentioning that during the period the sick textile mills have been managed by the Government, they have shown good working results in terms

[Shri B. P. Maurya]

wiping out past accumulated losses. As per provisional figures available the 96 mills under the management of the Government have generated a net profit of Rs. 9 crores during April-August, 1974. National Textile Corporation has also undertaken a comprehensive programme of modernisation and rehabilitation of these sick textile mills.

Before I conclude I want to refer to the point raised by Shri Madhu Limaye, the price policy has been their main slogan in their political working. We agree that there should be a price policy whereby the NTC could provide good quality cloth to the consumer at the lowest possible price, and it will be the endeavour of the NTC to lower down the prices by 25 to 30%. He referred to priority being given to the wages of the workers and we shall discuss that in details when we come to the clauses.

With these words I beg to move :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the owners in respect of the sick textile undertakings specified in the First Schedule with a view to re-organising and rehabilitating such sick textile undertakings, so as to subserve the interests of the general public by the augmentation of the production and distribution, at fair prices, of different varieties of cloth and yarn, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the owners in respect of the sick textile undertakings specified in the First Schedule with a view to re-organising and rehabilitating such sick textile undertakings, so as to subserve the interests of the general public by the augmentation of the production and distribution, at fair

prices, of different varieties of cloth and yarn, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Mr. Chairman, this Bill has been brought forward to nationalise the sick textile mills. I want to point out that merely by taking over or nationalising the sick textile mills, the problem of the textile industry or the problem of supply of cloth in adequate quantities to the people at reasonable prices will not be solved.

The textile industry, as we all know, is one of the largest industries in our country. How is it that 103 mills, which account for 20 to 25 per cent of the total mills, have become sick so that they have to be taken over by the National Textile Corporation? When the enquiry was conducted by the Government under the Industries (Development and Regulation) Act, how many of these mills were found to be sick because of corruption and mismanagement by the owners and in how many cases action was taken against the management for corruption and mis-handling of the money of the shareholders or depriving the workers and employees of their dues by way of wages, provident fund contribution etc. As far as my knowledge goes, not even in one case has any action been taken against any single mill-owner of these sick mills. This Nationalisation Bill is nothing but a rescue operation of the owners for their nefarious activities of defalcating funds. They will be resurrected by the Government, by first taking over and then by nationalisation. They are going to get about Rs. 40 crores as compensation as per the Bill. Even after take-over more than Rs. 67 crore¹ were given as loans by the Government and other financial institutions.

How are they going to take back those amounts? I do not find anything in the Bill that any such measure is going to be taken

As regards the basis of compensation, I have seen how it is amusing to note that even Rs. 1000 will be given as a token compensation but, just now, the hon. Minister, while replying to Shri Madhu Limaye, said that post-take-over dues will be paid to the workers, if there are any. My question is : What will you do about pre-take-over dues ? You have said that you will pay gratuity to workers in full. What about the provident fund money ? What about their earned wages ? What about their leave wages ? Have you ever taken care to go through the matter as to what are the dues of the workers for the pre-take-over period ? I know, in many cases, the workers who worked, who spent their whole life there, are not getting their provident fund money even after two or three years of the taking over of the mill by the Government.

What is the provision here ? You have given priority to the secured loans which means bank loans. You have given no priority to the dues of the workers. That should be the first charge. Whatever amount may be available, the dues of the workers should be the first charge. You have not said in part B of the Second Schedule that the dues of the workers will be the first charge. You have put it in the fourth category, wages, salaries and other dues to an employee, then, revenue taxes, etc. etc. In the third category, you have put "secured loans" which means liquid money that was taken from some financial institutions by the management.

Why not you put the dues of the workers in the first category ? That should be the first charge.

There are so many cases, hundreds of workers, where the workers did not get their earned wages; they did not get their leave wages and other dues. You say that you have taken care of the cause of workers. I say, you are giving hoax and bluff.

Then, you have mentioned about modernisation and rationalisation. What does

modernisation and rationalisation mean. You will spend lakhs of rupees on importing machinery from outside. What for I know, in many cases, ordinarily 3 or 4 looms are run by one worker. In the name of modernisation, the machines would be imported so that even to the extent of 25 to 27 looms would be run by one single worker. So, by modernisation and rationalisation, you would reduce the complement of workers in a particular factory or mill. I have given an amendment that in no case, in the name of modernisation, in the name of rationalisation, in the name of making improvement in the factory, you will take any step so that any worker may lose his job. Some years back when this question of rationalisation came in Bombay, the textile workers fought against it. You can see what was the number of workers 15 years back. You go through the statistics and you will find that it has come to half. So, in the name of modernisation and rationalisation, if you dispense with the service of a large number of workers, what is the good of it ?

Then, you say that you are taking it over to supply to the consumers, cloth at a fair price. What is the fair price, I do not know. Mr. Madhu Limaye has spoken enough and given certain figures. I do not want to go into the details. It is also a hollow slogan like "Garibi Hatao."

So far as the functioning of the National Textile Corporation is concerned, we know how much corruption is prevalent there. Two years back one Mr. Tripathi who was the Chairman had to resign because of nepotism and corruption. What is the guarantee that the National Textile Corporation will function properly and there will be no corruption and that the money that will be spent for these mills will be properly utilised for maintenance, etc. ?

Coming to the cost, I may say that no provision has been made here to see that a certain percentage of production is done or allocated only for production of standard cloth which can be sold at fair price to

[Shri Dinan Bhattacharya]

the poor consumers. Uptill now in these mills that have been taken over by the Government—in some cases by the State Governments and in many cases by the Central Government—in how many cases did you produce the cloth which you sold at fair price? I know. I have personal experience. I have gone to some mills and seen it. Only in a very few cases, just for a show to the public, they open retail shops wherefrom people are supposed to get the cloth at fair price. But how many persons get it? It is only a show. So my point is that the production should be regulated in such a way that the maximum is produced for the ordinary consumers at fair price. The rich people can manage themselves from the smugglers and other sources. But the ordinary people, the poor people the poor peasants, cannot get it. So, a guaranteed production of standard cloth to be sold at a fair price, must be made by the Government.....

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): Do you want smuggling to be allowed? you say that the rich people may get from the smugglers.

SHRI DINAN BHATTACHARYYA: Smuggling will continue and you will get your fine cloth from them. Only you have to take the trouble of going to Bombay or Gujarat—the sea-coast—and you will get it.

Enough has been said how the consumption figure has come down from 15 to 16 metres three or four years back to 11 to 12 metres per head now at the present moment. There has been abnormal increase in the cost of the cloth. The idea which you have given is very good—to arrange for the production in such a way that you may sell the clothes at fair prices and so on. But what is required is, you have got to implement it. That is the main thing. A guarantee has to be made here in this regard that a certain percentage of clothes should be given to the ordinary people, to the poor people, to the common people at a reasonably low price. That is our demand, Sir.

17 hrs.

Then I would respectfully submit this: Do not allow the big sharks, the big industrialists and the big monopolists to exploit our scarce foreign exchange resources. That is my main point. They do all these things for importing machinery and chemicals and other things. They use these scarce foreign exchange for the purpose of getting machinery from abroad, getting chemicals from abroad and not even 50 per cent of the foreign exchange spent are being earned. That is to say, we are losing this foreign exchange which is very scarce. We have got to stop all these things. This is my submission.

You have taken over certain spinning mills. They should produce yarn for the handloom sector, for the handloom weavers. Another point I want to mention is that the textile owners are now saying that they will bring down the prices and so on. But is also worth noting that the Government self increased the prices to 30 or 35 per cent, but now the mill owners are announcing to reduce the price of cloth from 10% to 40%. This is a joke, or anything else? Nobody has any reliance on your big promise that you will arrange distribution of the cloth at fair price and so on. So my point is this. You have to bring a check on these exorbitant profits that these textile magnates are reaping. You have to see that the textile industry as a whole is taken over and nationalised. Otherwise this problem will not be solved. The problem will be there and will be accentuated. At their very sweet will they will bring cloth to the market and prices will be controlled by them and as Mr. Madhu Limaye has said, they will dictate the terms for the price of cotton and they will dictate the terms what will be the price of finished goods in the textile mills.

So, you have to take such steps and such measures as are very necessary to see that these textile monopolists do not get further chance to exploit our people.

Before concluding I again want to repeat about corruption in the National Textile Corporation. There was corruption in these mills and these mills were sick. Now, you are handing over or giving the charge of these mills to the National Textile Corporation which is full of corruption. No report has yet been placed as to the functioning of this Corporation. Only from some sources we have learnt there is a serious type of corruption and the Government must try to put an end to this corruption.

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) महापति महोदय, मैं इस बिल की धारा 5 का मरुन विरोध करने हुए इस बिल का हृदय से समर्थन करना हूँ।

प्रमुख ध्यान ता यह है कि जब शासन किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने जाता है, तो उस में श्रमिकों के अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना श्रमिकों के सहयोग के राष्ट्रीयकरण सफल नहीं हो सकता क्योंकि श्रमिक ही ऐसी शक्ति जमात है, जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, वार्का लोग नहीं है। इस बिल में पहले मैंने मंत्री महोदय से श्रमिकों की ग्रेजुइटी, प्राविडेंट फंड और उन की जो दूसरी रकम निकलती है, उस के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने मद्रमति प्रकट की थी। वह भी एक श्रमिक खानदान में से है और श्रमिक के प्रति उन की सहानुभूति है। लेकिन मंत्री महोदय की स्वीच में वह बात नहीं आई, जिम की बात हुई थी और हम घाणा रखने थे।

मंत्री महोदय को सायद पता नहीं होगा कि इस सदन में मजदूरों के हित के इन्ने सुन्दर कानून बने हैं, जो दुनिया के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलते हैं। इस सदन और इन सरकार ने हर बाण में श्रमिकों की बड़ी सहायता की है

और उन को घाये बढ़ाने में भी बड़ी पहल की है। मैं सोलह बरस की उम्र से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि इस गर्वमेंट से अधिक श्रमिक हितैवी गर्वमेंट में ने कोई नहीं देखी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक की धारा 5 जैसी श्रमिक विरोधी धारा भी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। श्रमिकों के हितों के ऊपर यह एक जबरदस्त कुठाराघात है।

श्री धोडे दिन पहले कोलमाइन्ड का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन कोलमाइन्ड के श्रमिकों के लगभग 11 करोड़ रुपये प्राविडेंट फंड के बकाया में, जो कोलमाइन्ड के मालिकों से नहीं भरे थे। लेकिन सरकार जब राष्ट्रीयकरण का बिल लाई, उस में उस ने पिछली ग्रेजुइटी, पिछले प्राविडेंट फंड, लीव विद वेज, पेन्शन और बोनस आदि के सम्बन्ध में जो भी बकाया रकम उन मालिकों के द्वारा जमा नहीं कराई गई, वह सब मजदूरों की ओर सब दे रही है।

इसी प्रकार सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और उस के बाद बैंक कर्मचारियों को एक पिछले इयूज बराबर मिल रहे हैं। मैं नम्रता के साथ यह पूछना चाहता हूँ कि इन टैक्स्टाइल वर्कर्स ने, जो कुल वर्कर्स का एक चौथाई भाग है, इन 1 लाख 65 हजार परिवारों ने क्या पाप किया है और सरकार से क्या दुसमनी की है, जो वह 1 अप्रैल, 1974 से पहले के सब इयूज उन में छीन रही है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ईमानदार मजदूर कार्यकर्ता इस धारा का समर्थन नहीं करेगा। हम ने मजदूर आन्दोलन एक धर्म के तौर पर स्वीकार किया है एक

[श्री राम सिंह भाई]

पेशे या एक लीडरी के तौर पर नहीं। हम ने राष्ट्रीयीकरण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि सब से पहले हमारा राष्ट्र है और हिन्दू धर्म से जो गी का दर्जा है, उस के समान हम उद्योग और मजदूरी की रक्षा करेंगे ?

राष्ट्र हित के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम मजदूरी को यह कहने के लिए भी तैयार हैं कि ये राष्ट्रीय मजदूरी है इन में आप समानता और मेटन से काम करिए और ऐसा बे कर रहे हैं। मने यहां के कन्ट्रोलर यह नहीं कह सकते कि मजदूर ऐसा नहीं कर रहे हैं। 7 मिले हमारे प्रदेश में है। अच्छे से प्रच्छा प्रोडक्शन बढा है। अच्छी एफिशियन्सी और डिमिनिशन बगैर है। लेकिन मुझे कुछ यह है कि मजदूरी की पीछे की रुझाई क्यों छिनी जा रही है ? एक मजदूर बुड्ढा हो गया है। गान न स्ट्रेडिंग ब्रांडर में यह भी डान दिया है कि 56 वर्ष की उम्र होने पर श्रमिक को रिटायर कर दिया जाएगा। उस के रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। वह जाता है। लेकिन उस का 20 वर्ष का प्राविडेंट फंड जो जमा है उस से एक पाई उस को नहीं दी गई है और उस से कहत हैं कि वह तुम्हे नहीं मिलेगा। ग्रेच्युटी का जो कानून बनाया है इस मदन ने उन कानून के अन्दर यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्टेट सरकार द्वारा जो भी कारखाने चलाए जाते हाने, जहां भी कंट्रोलर के द्वारा कारखाने चलन हाने उन सब में श्रमिकों को ग्रेच्युटी मिलेगी। यहाँ यह सब क्या है ? बहुत नाजुब स्थिति है और अगर इसी तरह हम धारा को आप पास कर रहे हैं तो मजदूरी का सहयोग आपने नहीं मिलने वाला है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस दिन यह राष्ट्रीयकरण अध्यादेश निकाला हिन्दुस्तान में मिलों के अन्दर हड़तालें हुई थीर हड़ताल होने के बाद नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया। वह सर्कुलर 8 नारीख को मिलों के बोर्ड पर लगाया गया और उन में यह कहा गया कि भारत सरकार के एटार्नी जनरल ने अपनी राय दी है कि मजदूरी की ग्रेच्युटी और प्राविडेंट फंड की रकम घिनेगी और हम आप को बेने नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन देगा अध्यादेश लागू हो जाने के बाद नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की तरफ से उन मिलों के ऊपर यह नोटिस लगाए गए। मजदूर काम पर गए मेरे पास एटार्नी जनरल महोदय की भिकारिश है। उस में उन्होंने कहा है कि आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और यह उन के लिए अध्यादेश है लेकिन ग्रेच्युटी कानून के अनुयायता आप को ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। ग्रेच्युटी देने का मबाल आज पैदा नहीं जाना है। ग्रेच्युटी हर महीन नहीं दी जाती है हर मान नहीं दी जाती है। ग्रेच्युटी तो तब दी जाती जब मजदूर रिटायर होगा। वह उस पर कि मालिक का बढ़ता फिरेगा। उस मिल के बारे एमेंट तो आपने रहे है तो एमेंट के माब प्राविलिटी की भी आप को जबाबदारी है। दूसरी बात यह है कि आप ने जो भी कानून बना रखे है उन कानूनों के अनुसार कोई मजदूर ग्रेच्युटी के लिए बीच में कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट मालिक अगर प्राविडेंट फंड की रकम जमा नहीं करा रहा है तो मजदूर कोर्ट में जा कर दावा नहीं कर सकता, कि आप हमें प्राविडेंट फंड की रकम दिववाइए। यह सारी जिम्मेदारी

श्रीर अधिकांश केन्द्रीय सरकार श्रीर राज्य सरकारों की है कि जो मालिक समय पर जमा नहीं कर रहे हैं उन की बसूची त्रिड रेवेन्यू की तरह करें। पारी जिम्मेदारी नो कानून का पालन कराने की प्राप की है, राज्य सरकार की है।

इस सदन के अंदर हम ने बार बार कहा कि अनुक मिलें है जिन्होंने प्राप की 20 करोड़ से ज्यादा जो प्राविडेंट फंड की रकम है वह इन मिल मालिकों ने जमा नहा कराई है और जब यह टेक ओवर का बिल आया तब भी मैंने कहा। मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम इन्हें मुआवजा देंगे। उन में से मांग बसू न कर लेंगे। लेकिन यह जो मुआवजा दिया जा रहा है उस में से तो वह पूरा नहीं होता है? अगर प्राप प्रथम प्राविडेंट में भी मजदूरों की रकम रखें तो भी नहीं होता है जो रबी भी नहीं गई है। इस में हमारा कसूर क्या है? मैं प्राप को जानकारी देना चाहता हूँ कि प्राविडेंट फंड की जो रकम है कानून के अनुसार पांच वर्ष से कम की नौकरी हो या पांच वर्ष से कम का प्राविडेंट फंड जमा हो तो उन के उपर मिल मालिक का हिस्सा नहीं मिलेगा। पांच और दस के बीच हो तो 50 प्रतिशत मिलेगा और 20 से कम पर 75 प्रतिशत 20 वर्ष की पूरी नौकरी हो जाए तो हीसेंट परसेंट उमे मिलेगा। 1952 में प्राविडेंट फंड ऐक्ट लागू किया और 1971 में 20 वर्ष हो गए सारी रकम प्राविडेंट फंड की मिला के हिस्से के माध मजदूरों को लौटा दी जानी चाहिए थी। यह मांग हमने की थी। लेकिन वह लौटाई नहीं गई। प्राप ने उमे रखा तो वह जिम्मेदारी देने को प्राप की है।

इस के बाद मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, बड़े मजे की बात है, एक मिल है, उस मिल का मालिक उस मिल को बद-इजाबी से लबाह कर रहा है, बरबाद कर रहा है और वह 1949 में नोटिस लगाता है कि यह मिल मैं बन्द कर रहा हूँ। मैं केन्द्रीय सरकार के पास जाता हूँ, अम मंत्री से मिलता हूँ,

बिन मंत्री से मिलता हूँ, उद्योग मंत्री से मिलता हूँ, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। प्राचीर में केन्द्रीय सरकार के आदेश में एक त्रिदनीय समिति बनाई। उस की रिपोर्ट के अनुसार 1950 में इम मिल के 1200 मजदूरों की छंटनी एक साथ की गई बिना ग्रेजुइटी के। उस हिमाब से प्रतिमास 1 लाख 8 हजार रुपए की वेतन बचत की जो प्रति मास 12 लाख 96 हजार रुपए हुई। उस के बाद भी हमने इतना बुरा हाल हुआ कि वह मिल ठिकाने नहीं पड़ी। 1957 में जब मे यहाँ हाउस में आया उस वक्त 5 लाख 78 हजार रुपए प्राविडेंट फंड के उस में बाकी थे और लगभग 1 लाख रुपए 8 एम आई की रकम बाकी है? मैंने इस हाउस में निवेदन किया कि इस के लिए कुछ करना चाहिए। मिल चली जाएगी बन्द हो जाएगी। सरकार ने 1958 में एक कमेटी बनाई अरविंद नरसिंह लाल भाई की। उन्होंने जांच की। वह जांच रिपोर्ट मेरे पास है उस के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया? फिर 1959 में एक और कमेटी बनाई जिन के सदस्य पार्लियामेंट के मेम्बर सामान्नी साहब थे। उस में भी कुछ नहीं हुआ। फिर 1960 में एक अरक-निया कमेटी बनाई उसी मिल के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1970 में मोदी कमेटी बनाई जब तक 16 लाख 55 हजार 992 रु० केवल प्राविडेंट फंड के उम बिल पर हो गए। 1971 के बाद 1972 में टेक ओवर करते हैं, उस समय 53 लाख से अधिक बकाया थे? यह मामला 1950 से चल रहा है लेकिन टेक ओवर किया 1972 में। तो इस में मजदूरों का क्या दोष है? अगर प्राप बसूली के मजदूरों को अधिकांश दे दी जाए तो वे उस मिल मालिक को एक दिन में निकाल कर बाहर करेंगे। हम ने तो यह भी कहा कि प्राप हमें मिल दीजिए, मजदूर चलाने के लिए तैयार है। लेकिन मर्बन-मेंट चलाने देने के लिए तैयार नहीं थी? किन्तु 1972 में जब इस का टेक ओवर किया उस समय 33 लाख 42 हजार 296 रुपए मजदूरों के प्राविडेंट फंड के बकाया थे। जब केन्द्रीय बा

[श्री राम सिंह झाई]

राज्य लेबर मिनिस्टर जाते हैं मजदूर बसूली के लिए हड़ताल करते हैं, प्रोसेशन निकाल कर उन के पास ले जाते हैं श्रीराम कहते हैं कि यह मिल मालिक प्राविडेंट फंड जमा नहीं करा रहा है, वह इस से वसूल किया जाए। यही नहीं थाप ने टेक ओवर किया। उस के बाद भी क्या हालत है? एक स्वदेशी मिल है। जिस रोज 1966 में उस मिल को टेक ओवर किया उस रोज 8 लाख 16 हजार 910 रूपए उस पर बकाया थे। (श्रवणधन) मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। अपनी पार्टी की तरफ से मैं खास बकता हू। कोई ऐसी बात जो माननीय सदस्यों ने कही हो वह मैं नहीं कह रहा हू। और मैं यह मानता हू कि जो मैं कह रहा हू वह कोई और माननीय सदस्य कहने वाले भी नहीं हैं।

जब टेक ओवर किया तो 8 लाख 16 हजार तो प्राविडेंट फंड की रकम बकाया थी? थाप 1966 से इस मिल को चला रहे हैं लेकिन 1973 का हिसाब मैं बनाना हू 37 लाख 39 हजार 912 रूपए प्राविडेंट फंड के उस पर है और 15 लाख 36 हजार 400 रूपए ईएम आई के है। ये 53 लाख हो गए। जब टेक ओवर किया तब तो कुल 11 लाख थे और अब है 53 लाख तो प्राविडेंट फंड और ई.एस.आई. के और पांच वर्ष के बकाया बोनस के मिला कर हो गए 83 लाख। इस की जबाब दारी किमकी है? अगर उन के मालिक के समय के 8 लाख रूपया निकाल भी दिया जाए तो बाकी रूपया तो थाप दीजिये थाप उसका मुद्दा क्या क्या देने एक हजार रूपया कुछ सदस्य कह रहे हैं कि उस को प्रथम प्रायोरिटी दी जाये, थाप ने उस को एक हजार रूपया दे भी दिया तो जिस मील में 2600 मजदूर काम करते हैं, वहाँ एक एक रूपया भी मजदूर के हिस्से में नहीं आयेगा—सरकार इसे देखना चाहिए।

यहाँ एक मील के बारे में और बतलाना चाहता हू—मैंने उस के बारे में इस सदन में

बार बार कहा है कि और मंत्री जी को उस की बँलैम शीट भी दी थी। माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी इस मामले में ज़ेरा समर्थन किया था इस मील का नाम है—माल्हा यूनाइटेड मिल। 1968 में उस मील के ऊपर 8, 40,070 रु० प्राविडेंट फंड का और 5, 07, 978 रूपया ई० एम० आई० का बकाया था। नियम के अनुसार जब किसी मजदूर की लड़की की शादी होनी है तो प्राविडेंट फंड की रकम में से उस को शादी के लिए रकम निकालने का अधिकार है। इस मिल के मजदूरों को लड़कियां कुंवारी बैठी रही। लेकिन उस मजदूर को उस की जमा रकम में से एक रूसा भी नहीं मिला, मैंने इन सदन में प्रश्न का बार इस सवाल को उठाया मिल मालिक इस रकम को जमा नहीं करा रहे है और सरकार को वसूल करने की कोई जिम्मा नहीं है। सरकार चाहेती लैड रेवेन्यू की तरह उस रकम को वसूल कर सकती है लेकिन सरकार ने वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की? नियम के अनुसार रकम काटने के 15 दिनों के अन्दर उसे सरकारी खजाने में जमा करना चाहिए। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उन मिल मालिक का 6 महीने की सजा हो सकती है थाप लतनाशये थाप ने कौन से मिल मालिक का कठघरे में लाकर खड़ा किया? 1966 में उस की तरफ 18 लाख रूपया बकाया था 1967 में वह रकम 31 लाख हो गई, 1964 में 50 लाख हो गई, 1970 में 61 लाख हो गई 1972 में 80 लाख 87 हजार 250 रूपए हो गई। यह तो मिक प्राविडेंट फंड की रकम थी, ई० एम० आई० में उस की तरफ 31,55,292 रूपए बकाया था। ई० एम० आई० का रूपया जमा न होने से मजदूर को दवाई भी नहीं मिल सकती, जब कि उन के बँतन में वह दरया काटा जाता रहा। आज मजदूर काटी हुई रकम से कारखाना चल रहा है और जब मजदूर बुड्डा होकर जाता है तो उस से कहा जायेगा—भीसे खानी ऊँचे हाथ करके फाटक से बाहर निकला। इन म बड़ा धन्याय और क्या हो सकता है।

सभापति जी, मंत्री महोदय भी एक श्रमिक परिवार के हैं, और यह सरकार भी नहीं चाहती कि गरीबों के साथ श्रम्याय हो—तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप कारखानेदारों को मुद्रावजा दे रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर को अपने घर के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं मजदूर की यह कीमत आज हमारे मुल्क में है। एक मिल की तरह 83 लाख 26 हजार 312 रुपया प्रावीडेंट बकाया है, लेकिन उस को भी मुद्रावजे का हजार रुपया मिलेगा।

मे आप से पूछना चाहता हूँ—प्रायोरिटी का क्या मतलब है? माल्वा मील की तरह 1972 में मजदूरों का 1,03,20,553 रुपया बकाया था, लेकिन उस को मुद्रावजा मिलेगा—94 लाख रुपया, जिस में से 1, 12,52,000 रुपया तो आप का सिन्डिकेट लोन है, जो आप मजदूरों की रकम में पहले वसूल करेंगे—फिर मजदूर के लिए क्या बचेगा। मे माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस पर फिर से विचार करें। जो आप का राष्ट्रीकरण है उस की मकलना मजदूरों के महयोग पर निर्भर करती है, अगर मजदूरों को नाराज करेंगे, उन को के तन में से काटी गई रकम उन को नहीं मिलेगी और उन्हें घेच्युटी भी न देगे तो अन्त में उन को खाली हाथ फाटक से बाहर जाना पड़ेगा, तो इस में बुरी बात क्या हो सकती है ?

मे माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ—1972-73 का वर्ष टैक्सटाइल मिलों के लिए इतने फायदे का गया है, कि ग्रामद टैक्सटाइल मिलों के इतिहास में ऐसा वर्ष नहीं गया 1943 और 1948 के बाद 1972-73 का ही साल ऐसा साल है जिस में टैक्सटाइल मिलों ने काफी फलदा और आप के राष्ट्रीकृत मिलों के मजदूरों ने इस में बड़ा जबरबस्त सहयोग दिया है। मे आप को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि किस समय इन मिलों का टेक शीवर हुआ था, उस समय कुछ प्रमह मजदूरों ने कहा था कि

गर्बनमेंट द्वारा कारखाना चलाने में हम अपना बेतन कटाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपना बेतन कट कर सहयोग दिया।

सभापति महोदय आप कितनी देर और चाहते हैं ?

श्री रमसिंह भाई : साढ़े पांच बजे तक।

सभापति महोदय : आप की पार्टी की तरफ से 22 लोग बोलने वाले हैं—अब सब को मौका दिया जाए तो 7 मिनट हर एक के हिस्से में प्राते हैं....

श्री रमसिंह भाई : एक मिनट और दे दिजिए।

सभापति महोदय मैंने 20 मिनट आप को दिए हैं—आप स्वयं सोच सकते हैं कि आप ने कितने माथियों का समय ले लिया है।

श्री रमसिंह भाई सिकं एक मिनट और लूंगा।

मे एक बात और पूछना चाहता हूँ—मिलों को आप जो मुद्रावजा देना चाहते हैं वह किस हिसाब से दे रहे हैं। मैंने देखा है अहमदाबाद जूंपिटर मिल को जिस से केवल 1325 लम्ब है, उस को 2 करोड़ 35 लाख 68 हजार मुद्रावजा दे रहे हैं, जब कि इण्डिया यूनाइटेड मिल को जिस में 6325 लम्ब है, केवल 1 हजार मुद्रावजा दे रहे है। इसलिए मे जानना चाहता हू कि सिक-टैक्सटाइल मिल के मालिकों को जो मुद्रावजा आप देने जा रहे हैं, उस का हिसाब कैलकुलेशन क्या है, उस का तरीका क्या है ?

SHRIMATI ROZA DESHPANDE (BOMBAY CENTRAL): In the first instance I want to welcome this bill. Goernment have taken quire sometime to arrive at this conclusion that they should nationalise these mills. They did not start with the idea of helping labour. They started with the idea of

[Smt. Roza Deshpande]
ing the mill on lease and helping mill owners who were losing. This very theory has brought about certain great failures in this Bill. For instance a mill in Bombay, Sakseria Mill, was taken on lease for one year because the mill owners w . Then the Government made profits in just one year and they returned it to the mill owners. Again he made losses and again the Government took it up on lease and later on handed over to the mill owner. Then that mill was closed for many years. The General Secretary of the A.I.T.U.C. Shri Dange had to climb the gates of that mill and told the Government that it was high time they took it over and nationalised it. That is why I say they started with the idea of helping the mill owners and not helping the workers.

MR. CHAIRMAN You can continue tomorrow.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

C.B.I. INQUIRY INTO LAND DEAL SCANDAL OF CUTTACK STATION OF A.I.R.

MR. CHAIRMAN : We will now take up half-an-hour discussion. Before we take it up I should like to point out to the House that at least I would wish to go by the rules and I hope you would cooperate.

Rule (55) says :

“There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact.”

Now, if we have to finish this in half an hour, I would need your cooperation; to be strictly within the rules, to make a short statement I will give you five minutes.

SHRI SURENDRA MOHANTY (KENDRAPARA) : Five minutes would not do.

MR. CHAIRMAN : I would not go beyond-half-an hour.

SHRI SURENDRA MOHANTY : I am grateful to you for your guidance But I can show you umpteen instances where.....

MR. CHAIRMAN : I am not concerned with those umpteen instances. I will go by the rules.

SHRI SURENDRA MOHANTY : How much time will I get ?

MR. CHAIRMAN : You will get ten minutes.

SHRI SURENDRA MOHANTY : I would like to preface my observations by the remarks that I have no intention to politicalise the issue, or scandalise any individual, institution or government, as far as this particular matter is concerned. My only intention is to put this All-India Radio land deal in Cuttack in its legal perspective and to urge upon the hon. Minister to lay the copy of the CBI Report on the land deal on the Table of the House so that we all know the facts. What I am interested with, and I am sure what the House is interested with, is to know the facts. I have no intention, I repeat, either to scandalise anybody or to politicalise the issue.

The genesis of the matter is like this. It will be recalled that in the year 1969 the Government of India had acquired about two acres of land in Cuttack for the purpose of constructing staff quarters for the All India Radio employees at